

झारखंडगज

ट

असाधारण अंक

झारखंड सरकार

द्वारा प्रकाशित

4 मई,

1938 (श०) सं० या 366 राँची, बुधवार,

25 मई, 2016 (ई०)

विधि

(विविध)

विविध

-

अधिसूच

ना

25 मई, 2016

संख्या-एल०जी०-12/2016-103/लेज०-झारखंड विधान मंडल कानूननिलंबित अधिनियम, जिस पर
राज्यपाल 11 मई, 2016 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सार्वसाधारण कक्षा सूचना के लिये प्रकाशित
किया जाता है।

झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम-17, 2016)

प्रस्तावना

2

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

राज्य के विधिविभाग एवं उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योजना एवं
कार्यान्वयन, अनुवर्ण (निर्बोधन) तथा मूल्यांकन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, परामर्श और निधिकरण हेतु
उपयुक्त विधान के लिए अधिनियम।

चूँकि यह सम्योचित है कि सरकार, विधिविभाग, अकादमिक और विधिविभाग के
बीच सामूहिक सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने हेतु सरकार और विधिविभाग तथा विधिविभाग एवं
उच्च स्तरिय नियामक संस्थाओं के मध्य परचालनात्मक अंतराल के साथ (i) सरकार के नीति-निर्माण एवं
सापेक्ष योजनाओं में अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक उपाय को प्रोत्साहित करने, (ii) राज्य के सभी
उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य स्वायत्तता, जवाबदेह और समन्वयन को सुनिश्चित करने, और (iii) राज्य का

सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुषंग उच्च शिक्षा के मैट्रिपूणा विकास को निरदिशित करने के उद्देश्य से राय उच्च शिक्षा परिषद् का स्थापना का जाय।

भारतीय गणराय के 67वाँ वर्ष मझारखंड राय के ढवधानसभा तारा यह निनिलखत ढप मझ अधिनयमत हो:-

1. संक्षु नाम, ढवतार और ढारंभ:-

- यह अधिनयम झारखंड राय उच्च शिक्षा परिषद् अधिनयम, 2016 कहा जासकेगा।
- इसका ढवतार ढेह संपूणा झारखंड राय होगा।
- यह राय के शासकाय राजपद्द मझ अधिसूचना जारह होने का ितिथ से ढभावीहोगा।

2. पारभाषा - अगर इस अधिनयम के संदभ मझ अयथा अपेक्षत/आवश्यक हो:-

- ‘संभ संथान’ से आशय है वैसे संथान जो अपने शासी िनकाय के तारा संचालित व िनयंढुत ह।
- ‘ए आई एस एच ई’ से आशय है ऑलइंडया सव ऑनहायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा से संभ अखल भारतीय सवृण) जो भारत सरकार के मानव संसाधन ढवकास मंडालय का पहल पर का गई है।
- ‘शीष िनयामक संथान’ का अथ है िनयामक संथाजसे संसद के अधिनयम तारा ढविश्य ढकृति का संथाओं के अभशासन हेतु गठत ढकया गया हो।
- ‘अयद्’ का आशय वह ढयढ है जसे राय उच्च शिक्षा परिषद् के अधिनयम के आधार पर िनयुढ ढकया गया हो।
- ‘परषद्’ से आशय है - राय का ढवधायिका तारा गठतझारखंड राय उच्च शिक्षा परिषद्।
- ‘कायपालक िनदेशक’ यानी परषद् के सदस्य सिचव, जजनका िनयुढ राय उच्च शिक्षा परिषद् अधिनयम तारा सुनिठत ढावधान के तहत हो।
- ‘सरकार’ का आशय है झारखंड सरकार।
- ‘उच्च शिक्षा’ का अथ है - ढवसायिक, तकनीका या अय तरह के ढडईी या ढडलोमा के ढप मझ ढवढवतलय के मागदशान मझ ढाउ शिक्षा।
झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016
- ‘संथान’ यानी ऐसे संथान, जजनके तारा ढविभन ढकार के पायडम अथवा ढिशृण कायडम ढेतुत/ढेताढवत ढकये गये ह।
- ‘सदस्य’ से आशय राय उच्च शिक्षा परिषद् के सदस्य जजनमझ परषद् के अयद् और उपायद् भी सढमिलत ह।
- एम0आइ0एस0(ढबंधन सूचना तंहु) से आशय है कायडमता एवं ढभावी रणनीतिक िनणय लेने हेतु ढबंधन का सूचना तंहु।
- ‘एन ए ए सी’ से आशय है राडीय मूायांकन एवं ढयायन परषद्, जसका स्थापना ढविश्य उच्च शिक्षण संथान का ‘गुणवता ढेथित’ के ढेणी-निधाकरण के िलए का गयी है।
- ‘निजी ढवढवतलय’ से आशय है - राय के वैसे ढवढवतलय, जजनका स्थापना “झारखंड राय के िनजी ढवढवतलय का स्थापना और िनगमीकरण के िलए आदश मागदशान” के अनुष हुई हो।
- ‘िनयमन’ का अथ है वैसे िनयमन जो राय उच्च शिक्षा परिषद् तारा बनाये गये ह।
- ‘िनयम’ का अथ है वैसे िनयम जो राय उच्च शिक्षा परिषद् तारा िनिमत ह।
- ‘राय ढवढवतलय’ से आशय है - राय सरकार तारा संचालित, ढबंधित और िनयंढुत ढवढवतलय।
- ‘परिनयम’, ‘अयादेश’, ‘िनयमन’ से आशय है ढवढवतलय के वैसे परिनयम, अयादेश और िनयमन से जो ढकसी ढवढवतलय से संभ अधिनयम के अनुष जारह ढकये गये ह।

xviii. तकनीक ढवढवलालय का अथा वैसे ढवढवलालय से है, ँजनका ढथापना तकनीका िशढा और ढिंशिढण,

अनुसंधान, नवाचार, सावाजिनक और िनजी ढेढु के परामशक, उढमशीलता, सतत् िशढा कायढम, ढवायल

महाढवलालय/संढथान; और साढढ अंगीभूत एवं िनजी महाढवलालय/संढथान के माढयम से समाज मढ मूढय

ढिनमाण एवं सामाजक कढयाण के उढेढय से का गई हो।

xix. 'उपाढयढ' यानी राँय उाँच िशढा पारषढ अधिनयम के अनुसार िनयुढ उपाढयढ।

3. पारषढ का संढवधान:-

i. सरकार अधिसूचना के ढारा, उस ितिथ के ढभाव से जो इसमढ उढालढखत हो, पारषढ संढथाढपत करेगी, ँजसे

झारखढड राँय उाँच िशढा पारषढ कहा जाएगा।

ii. पारषढ एक ऐसी सढामिलत िनकाय संढथा होगी जो सतत् पद-ढािु अनुढम और सामाढय ढितिढा के तहत

तथाकिथत एक नाम के साथ संचालित होगी ँजसे वाद चलाने का अधिकार होगा और ँजसपर वाद दायर ँकया जा सकेगा।

iii. ढावधान के अनुढप पारषढ को चल और अचल सापढल ढहण करने और उस पर आधपयरखने का अधिकार होगा और इस ढावधान के अंतगत िनिमात कानून के अनुढप इसका सापढल को हढतांतरत करने

या ठेके पर देने तथा ऐसाकोई भी काय करने का अधिकार होगा जो इस अधिनयम के उढेढय का पूति के

िलए आवढयक हो।

4

झारखढडगजट(असाधारण)

बुधवार, 25 मई, 2016

iv. पारषढ का मुढयालय राँची मढ अवढथत होगा।

4. पारषढ के उढरदायिढव और काय:-

i. पारषढ के िनढनिलढखत उढरदायिढव एवं काय ढुगे:-

(a) राँय का सरकार, सरकार ढारा ढथाढपत ढवढवलालय, िनजी ढवढवलालय एवं अढय उाँच

िंशिढणसंढथान को सुझाव/परामश ढेना;

(b) राँय के अंतगत उाँच िशढा मढ सरकार, सरकार ढारा ढथाढपत ढवढवलालय, िनजी ढवढवलालय

एवं शीष िनयामक अभकरण का भूमिकाओं केबीच सामंजढय ढथाढपत करना;

(c) अढय उाँच िंशिढण संढथान का ढवायलता को अढुढण रखते हुए उढहढ उाँचिशढा का सामाढय

सुढवधाँ मुढैया कराना;

ii. उपयुढ दायिढव और कृढय के ढोढसाहन के िलए पारषढ को िनढनिलढखत उढरदायिढव लेने ढुगे:-

(a) सरकार के सुझाव या ढवढवलालय एवं अढय संढथान के अनुरोध पर ढवतःसंढान लेकर

राँय मढ उाँच िशढा के ढवकास हेतु 'राँय उाँच िशढा योजना'

(SHEP)

ढितिपाढ

ढत

एवं

ढढेतुत करना;

- (b) राँयकऱय संथानु तथा संब संथानु को उनका योजनाओं के ढितपादन काहेतुित एवं
अमल के िलए यथे/सहायता उपलब्ध कराना;
- (c) राँय उाच िशका योजना (SHEP)के अमल का ढेया का अनुवण ;
- (d) िनयतकालिक सांख्यिक का राँय एवं संथागत ढतर पर एककीकरण एवं उनका अनुरण ;
- (e) ढबंधन सूचना तंु(MIS)का सृजन एवं अनुरण ;
- (f) राऱीय ढतर के उाच िशका अभकरण (एजसिस) ढारा ढवकिसत मानदंड के आधार पर
संथाओं का मूयांकन करना ;
- (g) पारवितत हो रहे सामाजक पारऱय एवं अकादिक आवक्यताओं के अनुप पायचया
और पायडम मऱ सुधार हेतु सुझाव देना एवं उनका गुणवत्ता को बरकरार रखना ;
- (h) परकाओं का गुणवत्ता का सुनियन और परकाओं मऱ सुधार हेतु सुझाव देना ;
- (i) शोध और िशका ढाि (अधगम ढेया) के बीच सामंजस्य ढथापत करने हेतुआवक्यक
कदम उठाना ;
- (j) राँय के संथानु का ढवायता को संरुत करना और राँय के ढवऱवऱलय के पारिनयम, अयादेश और िनयमन का समय-समय पर पुनरका तथा िशका मऱ सामाजक
याय के उठेय का ढाि एवं िशका मऱ अकादिक उकृत के कायावयन हेतु समुचित
झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार,25 मई,2016

5

- सुधार के िलए सुझाव एवं ढवऱवऱलय तथा अया उाच िशका संथानु को पारिनयम,
अयादेश एवं िनयमन के िनमाण मऱ परामश देना;
- (k) उाच िशका के नये संथानु का ढथापना हेतु ढवीकृति ढदान करना ;
- (l) राऱीय मूयांकन एवं ढयायन पारष से ढवमश कर ढयायन हेतु सुधार केउपाय सुझाना ;
- (m) उाच िशका मऱ रणनीतिक िनवेश हेतु राँय सरकार को सलाह ;
- (n) राँय के उाच िशका संथानु और देश के भीतर एवं बाहर के संथानु के बीच अकादिक
ढकृति से संब काय हेतु मागदिशका ढवकिसत करना ;
- (o) इस अधिनयम के उठेय के अनुप िनिध का िनमाण एवं उपयोगिता हेतु ढेताव तैयार
करना ;
- (p) सरकार अथवा सरकार ढारा अधिकृत ळकसी अभकरण के ढारा ढदऱ अनुदान का ढवमुठ
के िलए सामाया िनयमावली का ढवकास तथा राँय उाच िशकायोजना (SHEP)के आधार पर
ढवऱवऱलय एवं महावऱलय को िनिध आवंठत करना ;
- (q) उठयिनिध का राँय के ढवऱवऱलय एवं अया उाच िशका संथानु को ससमय िनिध

अंतरण हेतु मणाली ढवकिसत करना ;

(r) उाच िशुा मल नीित-िनधारण और उहल समुचित सुसाय बनाने हेतु ढवशेषतः तथा

टेकहोडर के ढयापक संभाढवत परामशु माल करने के िलए ढवचार-ढवमशु, कायशाला एवं संगोडयु का आयोजन करना ;

(s) अकादमी, उलोग, कृष एवं ढवढान-ढेडु के बीच पारढपरक तालमेल हेतु मंच उपलढध कराना ;

(t) केडु तथा राय सरकार एवं भारत के केडु शासित ढदेशु के राडीय ढतर का शीषु िनयामक

संथाओं के तारा ढायोडजत और उमित ढविभुन कायडमु का समुवयन करना।

5. पारषु का गठन:-

पारषु िनढनिलढखत सदढयु के योग से बनेगा, यथा -

- i. अयु
- ii. उपायु
- iii. राय पारयोजना िनदेशक (राडीय उाचतर िशुा अभयान), जो पारषु के कायकार िनदेशक (सदढय सिचव) हुगे।

iv. ढधान सिचव, उाच एवं तकनीका िशुा ढवभाग

6

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

- v. कुलाधिपित तारा पाँच वैसे सदढय मनोनीत ढकये जांऐगे ढजनका ढवता अनुसरणीय हो, इनमल कला एवं संकृति, ढवढान एवं ढौलुगिक, नागरक समाज, उलोग तथा ढयावसायिक ढेडु के एक-एक सदढय हुगे।
- vi. सरकार तारा पाँच वैसे सदढय मनोनीत ढकये जांऐगे ढजनका ढवता अनुसरणीय हो, इनमल कला एवं संकृति, ढवढान एवं ढौलुगिक, नागरक समाज, उलोग, ढयावसायिक ढेडु के एक-एक सदढय हुगे।
- vii. राय ढवढवलयु के तीन कुलपित, कुलाधिपित तारा तीन वषु के िलएचढानुढमानुसार मनोनीत ढकये जांऐगे।
- viii. राय मल ढथाढपत िनजी ढवढवलय के एक कुलपित।
- ix. राय मल ढथाढपत तकनीका ढवढवलय के एक कुलपित।
- x. ढवायुशासी महाढवलयु के दो ढाचायु, कुलाधिपित तारा दो वषु के िलए चढानुढमानुसार मनोनीत हुगे।
- xi. अनुसरणयोढय ढवतापूणु ढयाति के तीन सदढय पारषु तारा सहयोडजत ढकये जांऐगे।
- xii. भारत सरकार के मानव संसाधन ढवकास मंडुलय तारा एक ढितिनिध का मनोनयन ढकया जाएगा।

6. अयु:-

- i. अयु अधिमानतः ढभावी नेतृवकारडगुणु से युड िेड अकादिमक या बौढक ढयाति के हुगे।

- ii. राॉय उांच िशःा पारषडु तारा गळठत तीन सदःयीय तलाश-सह-चयन सिमितताराभााU अनुशंसा
व चयन के आधार पर मुहयमंडुी, षवधानसभा अंयः और ढितपः केनेता से बनी सिमित अंयः
का चयन करेगी। पारषडु ढामाणक अकादिमक/बौःकःयाित के दो सदःयु को मनोनीत करेगी
जबळ सरकार एक ढयःळ का तलाश-सह-चयन सिमित मऱ मनोनयन करेगी। सरकार तारा नामजद
ढितिनिध सिमित कऱ अंयःता करेगा।
- iii. अंयः सरकार तारा िनयुः पारषडु के पूणाकालिक पदाधिकारऱ हंगे।
- iv. अंयः का कायकाल षवतार-रळहत पाँच साल के िलए होगा अथवा वे 70वषु कऱ आयु को ढााU कर
लऱ, इनमऱ से जो भीपहले हो।
- v. अंयः को उपःथत सदःयु के दो-ितहाई के ःपु/बहुमत के अःवयऱस ढेतऱव के तारा मतदान
से तथा तीन चैथाई सदःयु के कोरम के साथ पदमुःळ ँकया जा सकेगा।
- vi. अंयः को यह अधिकार होगा ँक वे पारषडु के िलए ँकसी उपयुः मामले पर ढितवेदनकऱ मांग
कर सकते हः और पारषडु कऱ कायढणाली मऱ सुधार हेतु सुझाव दे सकते हः।
- vii. अंयः पारषडु और कायकाऱणी सिमित कऱ बैठकऱ कऱ अंयःता करऱगे।
झारखळगजद(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016
- viii. अंयः को देय वेतनमान एवं ढऱे षवऱवऱलय के कुलपित के वेतनमान एवं ढऱे के समतुऱय हंगे। यळद वे सेवािनवृऱ ढयःळ हंगे तो उनके वेतन से पऱशन कऱ रािश घटा दऱ जाएगी।

7. उपांयः:-

- i. उपांयः िः ढामाणत उांचमान अकादिमक ढशासक हंगे। यळद उपांयः
गैरअकादिमकऱयःळ हो,
तो उऱहऱ उऱोग आळद ःः का पेशेवर होना चाळहए, ँजऱहऱअपनेकायःः का पयाऱU
अनुभव हो
(िनदेशक के पद से नीचे का न हो)।
- ii. सरकार उपांयः कऱ िनयुःळ तलाश सिमित (सचऱ किमटऱ) कऱ अनुशंसा पर करेगी। यह किमटऱ
पारषडु के अंयः (बतौर अंयः) और दो अंयः सदःयु के योग से गळठत होगी, ँजनमऱ से एक सदःय पारषडु तारा मनोनीत होगा तो दूसरा सरकार के तारा।
- iii. उपांयः का एक कायकाल षवतार-रळहत पाँच वषु का होगा अथवा वे 70वषु कऱ आयुके हो जाएँ।
- iv. उपांयः को अंयः अथवा पारषडु कऱ अनुशंसा के तारा हटाया/पदमुःळ ँकया जा सकेगा।
- v. उपांयः अंयः कऱ अनुपःथित मऱ पारषडु कऱ बैठकऱ कऱ अंयःता करऱगे।
- vi. उपांयः को देय वेतनमान एवं ढऱे षवऱवऱलय ढोफेसर के समतुऱय हंगे। यळद वे सेवािनवृत
ढयःळ हंगे तो उनके वेतन से पऱशन कऱ रािश घटा दऱ जाएगी।

8. कायपालक िनदेशक:-

- i. राऱीय उांचतर िशःा अभयान के राॉय पारयोजना िनदेशक हऱ पारषडु के पदेन कायपालक िनदेशक हंगे।

ii. काय[पालक िनदेशक पारषड के सदस्य सिचव हूंगे और पारषड के कायु के संयोजन का दायिख वहन करणगे।

iii. काय[पालक िनदेशक उन कृखु को भी सपून करणगे, जो समय-समय पर उहण आदेशित ठकये जाएंगे।

9. पारषड के पदाधिकार:-

पारषड के िनानिलखत पदाधिकार हूंगे, यथा:-

- अय
- उपाय
- काय[पालक िनदेशक (सदस्य सिचव)
- मशासनिक पदाधिकार
- वण पदाधिकार

8

झारखण्डगजट(असाधारण)

बुधवार, 25 मई, 2016

10. मशासनिक पदाधिकार:-

- मशासनिक पदाधिकार पारषड के पूणकालिक पदाधिकार हूंगे और ये वयवलय से मितियु अयठ हूंगे।
- मशासनिक पदाधिकार ठकसी महावलय अथवा वयवलय के ढनातकोर वभाग मण कम से कम 15वषु के िशण अनुभव रखनेवाले हूंगे तथा उहण वयवलय के मशासनिक कायु का पंच वषु का अनुभव भी होना चाँहए।
- मशासनिक पदाधिकार पारषड ढारा िनयु ठकये जाएंगे।
- मशासनिक पदाधिकार सामाय मशासन के मभार हूंगे और अय ढारा मदण शठयु व दायिख का िनपादन करणगे।
- मशासनिक पदाधिकार अपने पैतृक वयवलय से माउ होनेवाले वेतन तथा भण के अलावा मितियुठ भण माउ के हकदार हूंगे।

11. वण पदाधिकार:-

- वण पदाधिकार पारषड के पूणकालिक अधिकार हूणग।
- वण पदाधिकार के िलए कम से कम 15वषु का शैणक अनुभव होगा तथा उनके िलएवणीय मशासन, लेखा, अंकण और बजठय मठया कं बेहतर जानकार अपेठत होगी।
- वण पदाधिकार कं िनयुठ पारषड ढारा कं जाएगी।
- वण पदाधिकार लेखा वभाग के मभार तथा पारषड के लेखा जोखा मण िनपुणता हेतु उणरदायी हूंगे और वे अय ढारा िनधारित व मदत शठयु तथा दायिख का िनपादन करणगे।
- वण पदाधिकार अपने पैतृक वयवलय से माउ होनेवाले वेतन तथा भण के अलावा मितियुठ भण पाने के हकदार हूणग।

12. राँय परयोजना िनदेशालय:-

राँय सरकार के ढारा राँय परयोजना िनदेशालय का गठन ठकया जायेगा:

- गठन: राँय परयोजना िनदेशालय मण एक राँयपरयोजना िनदेशक हूंगे तथा जैसाउपयु ठो, आवकतानुसार सहायक किमयु के संयोग से िनदेशालय के मभावी संचालन हेतु राँय परयोजना िनदेशालय का गठन ठकया जाएगा।
- काय: राँय परयोजना िनदेशालय िनानिलखत कायु का िनपादन करेगा:-
 - राँय ढतरय परयोजना के ठयावयन का िनरण।
 - साँयकं आंकड़ तथा मबंधन सूचना तं के मितिवेदन कं देख-रेख।

□ आवश्यकतानुसार परियोजना अंकेक्षण क सेवा लेना।

झारखंड गजट (असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

13. तकनीक सहायता समूह:-

- राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विशेषज्ञ से युक्त एक तकनीक सहायता समूह का नियुक्त कर सकेगी।
- तकनीक सहायता समूह के संघटन का निष्पत्ति परिषद् द्वारा ठीक किया जाएगा।
- तकनीक सहायता समूह के कार्य होंगे:-
 - सूचना तथा कोष के निष्काह का देखरेख,
 - सामाजिक निबंधन सूचना तंत्र का रिपोर्ट आवश्यकतानुसार तैयार करना तथा
 - परिषद् को संचालन हेतु सहायता निदान करना।

14. मनोनीत सदस्य के लिए शर्त व बंधन:-

- मनोनीत व सामंजस्य सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः छह वर्ष का होगा, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य निम्नलिखित दो वर्ष के पश्चात् आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और रिक्त पद पर भर्तक कुलाधिपति द्वारा का जाएगा अगर निवृत्त होने वाले सदस्य कुलाधिपति द्वारा मनोनीत हों, और अगर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निवृत्त हो रहे हों तो सरकार सदस्य का नियुक्त करेगी और योंद परिषद् द्वारा सहसंयोजित सदस्य निवृत्त होंगे तो परिषद् उनका जगह पर नये सदस्य का सहसंयोजन करेगी।
- किसी भी अवस्था में परिषद् के बीस सदस्य राज्य के होंगे तथा अल्प पाँच राज्य राजनीति होंगे (राज्य के बाहर के)।
- मनोनीत और सहसंयोजित सदस्य लिखित रूप में परिषद् के अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकते हों पर उनका सदस्यता तब बनी रहेगी जब तक कि उनका इस्तीफा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत न हो कि ठीक किया जाता है।
- मनोनीत तथा सहसंयोजित सदस्य निम्नलिखित दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक शुल्क के हकदार होंगे।
- इस सेवा के अल्प शर्त एवं बंधन इस अनुच्छेद के निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित होंगे।

15. अयोग्यता:-

- कोई भी राज्य मनोनयन के योग्य न हो होंगे अथवा परिषद् का सदस्यता बनाये न हो रख सकेंगे, योंद उस समय वे -
 - मानसिक रूप से अक्षम हों;
 - करण न चुकाने का वजह से सजाया जाता हों;
 - किसी फौजदार अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए सजा कारावास का सजा पा चुके हों,
 इसके साथ ही नैतिक चरित्र न होना के दोषी पाये गये हों;

10

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

- (d) मंत्रालय अथवा अग्रिम मंत्रालय से एवं या उनके सहयोगी का पारषद के एक सदस्य का काम मंत्रालय से दारु अथवा वातावरण में रहता हो अथवा पारषद का ओर से जारु ओकसीसंवदा मंत्रालय उनका संलिता पायी जाय;
- (e) कोई राज्य ओकसी भी सरकार और व्यवस्थापक सेवा से दुःखानुहार अथवा लापरवाह का वजह से हटाया गया हो;
- ii. ओकसी भी ववाद या संदेह का अवस्था मंत्रालय ओक कोई राज्य उप अनुच्छेद (i) के अधीन अयोग्य है तो उस मामले मंत्रालय अग्रिम का निणय अंतिम होगा।
- iii. इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, कोई भी राज्य जो विधायक द्वारा थापत ओकसी व्यवस्थापक का नातक न हो, पारषद का सदस्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन मनोनयन का पात्र नहः होगा।

16. पारषद का बैठक:-

- i. पारषद का बैठक नियमावली मंत्रालय वृणत प्रावधान के अनुप निरुद्ध समय एवं स्थान पर होगी, ओकतु तीन महने मंत्रालय एक बैठक अवश्य होगी।
- ii. पारषद को समुचित निणय लेने का अधिकार अगर पारषद का बैठक मंत्रालय ओकसी सदस्य का रता का वरोध करना पड़े अथवा गठन मंत्रालय ओकसी मंत्रालय का हूँत हो और यह जानतेहु भी पारषद का कायवाह वैध होगी ओक पारषद का कायवाह मंत्रालय कोई राज्य, जो सदस्य होने का अधिकार न हो और वह बैठक मंत्रालय शामिल हो चुका हो या पारषद का कायवाह मंत्रालय भाग ले चुका हो।
- iii. पारषद का बैठक का संयोजन अग्रिम के परामश से कायकार निदेशक द्वारा ओकया जाएगा।
- iv. पारषद का बैठक का कोरम इसके कुल सदस्य का संख्या के एक तिहाई होगा और उपस्थित सदस्य के मतदान और सामान्य बहुमत से निणय लिये जा सकः गे।

17. पारषद के कमः:-

पारषद आवश्यकतानुसार किमय का नियुक्त करेगा जिससे ओक उसके काय का संचालन सुचारु ढंग से हो सके। पारषद के किमय का सेवा शत एवं बंधेज विनियम के तहत निधातरत हंगे।

18. पारषद का निध:-

- i. पारषद का निध मंत्रालय वो सभी धनराशियाँ हंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा मंदः और अग्रिम प्राणियाँ जो केतु सरकार अथवा ओकसी अग्रिम प्राधिकार, संस्थान या राज्य द्वारा दः गयी हो।
- ii. मंत्रालय वृणीय वष मंत्रालय सरकार पारषद को उतनी धनराशि उपलब्ध कर सकती है जो इसके सफल संचालन और ज्ञानेवार्य एवं कतः के निवहन के लिए जरु हो।
- iii. इस अधिनियम के उद्देश्य का पूर्ति के लिए ओकये गये सारे राज्य निध का राशि से चुकाये जाऐंगे और यँद कोई अतर राशि राज्य के बाद बची हो तो वृणत प्रावधान के अनुसार उसे निवेशित ओकया जाएगा।

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

11

19. वाषक लेखा और अंकः:-

- i. पारषद का लेखा ववरणी निधातरत मानदंड व प्रावधान के अनुप संचालित का जाएगा।
- ii. पारषद वाषक लेखा का ववरण निधातरत वृष और तरके से नियमानुसार तैयार करेगी।
- iii. पारषद के लेखा का अंक वष मंत्रालय एक बार सरकार का ओर से नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त अंकः द्वारा कराया जाएगा।
- iv. पारषद के कायकार निदेशक वाषक अंकः प्रतिवेदन मुँत ष मंत्रालय तैयार करःगे और उस प्रतिवेदन को पारषद के समः अगली बैठक मंत्रालय वचारण हेतु करःगे।

- v. पारषद् अंकेंद्रण ऋतवेदन मऱ दशाणी गयी ँकसी भी छुट अथवा अनियमितता को दूर करने हेतु समुचित कायवाहऱ करेगी।
- vi. अंकेंद्रक अपने अंकेंद्रण ऋतवेदन को पारषद् कऱ ँटपणी के साथ सऱयाऱपत करते हुऐनधाऱरत समयाविध मऱ सरकार को अनुशंसित करऱगे।

20. वाऱषाक ऋतवेदन:-

इस अधिनयम के अधीन पारषद् ऋतवषऱ अपनी वषऱ भर कऱ गितऱविधयऱ का ऋतवेदन तैयार करेगी तथा सरकार को यह ऋतवेदन सऱपेगी।

21. पारषद् के सदस्य व कमऱ सरकारऱ सेवक हऱगे:-

पारषद् के अऱयऱ, उपाऱयऱ, कायऱकारऱ िनदेशक, सदस्य, अधिकारऱ और कमऱचारऱ इस अधिनयम के तऱरा जारऱ ँकये गये ँकसी ऋवधान अथवा िनयम अथवा ऱविनयम या आदेश या िनदऱश के अनुऱप कायऱरत हऱगे, िनऱपादन करऱगे तो भारतीय दऱड संऱहता (1860का केऱऱुऱय अधिनयम XLV) के अनुऱछेद 21के आशयानुसार सरकारऱ सेवक समझे जाऐंगे अथवा सरकारऱ सेवक समझे जाने के दावेदार हऱगे।

22. ऱविनयम बनाने कऱ शऱऱ:-

पारषद् सरकार तऱरा अऱऱ अनुमोदन ऋऱऱ कर ऱविनयम बना सकेगी ँकंतुइस अधिनयम के ऋवधानऱ और िनयमऱ अथवा इसके उऱऱेऱयऱ को पूरा करने कऱ ँऱऱ से वह असंगत न हो।

23. िनयम बनाने कऱ शऱऱ:-

- सरकार, अधिसूचना के तऱरा इस अधिनयम के संपूणऱ अथवा ँकऱहऱं उऱऱेऱयऱ कऱ पूऱितऱ के िलऐ िनयम बना सकेगी।
- इस अधिनयम के अंतगऱत बनाऐ गए ऋऱयेक िनयम को यथाशीऱ रांय कऱ ऱवधाऱयिकाके समऱ ऋऱतुत ँकया जाएगा जब सऱऱ का पूणऱ काल चूदहऱदनऱ कऱ कुल अविध का हो जो ँक ँक सऱऱ अथवा दो लगातार सऱऱ मऱ हो, और अगर, इस सऱऱ कऱ समाऱऱ के पहले ऱजसमऱ इसे पेश ँकया जाता है याजो सऱऱ ठऱक इसके बाद आता है, ऱवधानसभा कानून मऱ कोई संशोधन करती है या फैसला ँकया

12

झारखऱडगजट(असाधारण)

बुधवार, 25 मई, 2016

जाता है ँक कानून नहऱं बनना चाऱहऐ तो वह (कानून)संशोऱधित ऱप मऱ हऱ ऋभावी होगा अऱयथाऱनऱऱभावी होगा जैसा मामला हो, हालांऱक इस तरह का कोई संशोधन या ऱवलोपन कानून के तहत ँकये गये कायऱ कऱ वैधता के ऋत पूवाऱह से रऱहत होगा।

24. अऱचनऱ/बाधाऱ को दूर करने कऱ शऱऱ:-

- इस अऱयादेश के ऋवधानऱ को ँडयाऱऱवत करने मऱ यऱद कोई बाधा उऱपऱन होती है तोसरकार आदेश के तऱरा ऱऱथित कऱ आवऱयकतानुसार ऐसा कुछ भी नहऱं करेगीजो इस अधिनयम के ऋवधानऱ के अनुऱप नहऱं हो, और अऱचन को दूर करने के उऱऱेऱयऱ से आवऱयक ऋतीत होता हो।
- उप-अनुऱछेद (1) के अंतगऱत िनगऱत ँकये गये ऋऱयेक आदेश को इसे बन जाने के बाद यथाशीऱ ऱवधान सभा के समऱ ऋऱतुत ँकया जाएगा।

झारखंड राँयपाल के आदेश से,

ऑदनेश कुमार

िसंह,

मंधान सिचव-सह-

विविध परामशक

विविध (ववधान)

ववभाग, झारखंड,

राँची।

अि
ध
सू
च
ना

2

5

म

ई

,

2

0

1

6

संख्या-एल0 जी0-12/2016-104/लेज--झारखंड ववधान मंडल द्वारा यथापारत और राँयपाल द्वारा
ऑदनांक-11 मई, 2016को अनुमत झारखंड राँय उाँच िशता परषड अधिनयम, 2016का िनानाँकत
अंईेजी अनुवाद झारखंड राँयपाल के मंधाधिकार से इसके द्वारा मकािशत ऑकया जाता है, वजसे
भारतीय संवधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) केअधीन उऑ अधिनयम का अंईेजी भाषा मा मंधाधिकृत
पाठ समझा जायेगा।

The Jharkhand State Higher Education Council Act, 2016

(Jharkhand Act-17,2016)

PREAMBLE

An Act to make suitable provisions for enforcing & planning, monitoring and evaluation,
quality

assurance, advisory and funding functions in Universities and other Technical Higher Educational
institutions

of the state.

Whereas it is expedient to establish a State Higher Education Council as a collective of
Government,

Universities, Academics and Experts in order to forge a synergetic relationship among them by
occupying an

operational space in between the Government and Universities and between Universities and apex
level

regulatory bodies with the object of (i) promoting academic excellence and social justice by the Government in

policy formulation and perspective planning, (ii) ensuring the autonomy, accountability and coordination

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

13

among all institutions of higher education in the state, and (iii) guiding the harmonious growth of higher education in accordance with the socio-economic requirement of the state.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Seventh Year of Republic of India as

follows.

1. Short title, extent, and commencement -

- (i) This Act may be called the Jharkhand State Higher Education Council Act, 2016.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force on such date the State Government may, by notification in the official

2. Definitions - In this Act unless the context otherwise required:-

- (i) 'Council' means the Jharkhand State Higher Education Council established by State Legislature.
- (ii) 'Higher Education' means education, whether professional, technical, or otherwise leading to the obtaining of any degree or diploma from the University.
- (iii) 'State Universities' means the Universities run, managed and controlled by the State Government.
- (iv) 'Private Universities' means University in the state established according to the "Model Guidelines for the establishment and incorporation of Private Universities in the State of Jharkhand".
- (v) 'Technical University' means University established with the objectives for value creation and welfare in society through technical education and training, research, innovation, public and private sector consultancy, entrepreneurship, continuing education programmes,' autonomous Colleges/Institution and affiliating constituent and private Colleges/Institutions.
- (vi) 'Affiliated Institutions' means the institutions which are run and controlled by their own Governing Bodies.
- (vii) 'Institution' means an institution with offers various kinds of courses or training programme.
- (viii) 'Member' means a member of the State Higher Education Council and includes the Chairman and Vice-Chairman.
- (ix) 'Chairman' means the Chairman of the Council appointed as per State Higher Education Council Act.
- (x) 'Vice-Chairman' means the Vice-Chairman of the Council appointed as per State Higher Education Council Act.

(xi) "Executive Director' means Member Secretary of the Council appointed under the provisions laid

down by State Higher Education Council Act.

(xii) 'Government' means the Government of Jharkhand.

(xiii) "Apex Regulatory Institutions' means the regulatory Institutions created by the Act of

Parliament for the governance of institutions of a particular nature.

(xiv) "Statutes', "Ordinances', "Regulations' of a university means the Statutes, the Ordinances, and

the Regulations issued under the respective Acts of a University.

(xv) 'Regulations' of the Council means the regulations made by the State Higher Education Council,

(xvi) 'Rules' means the rules made by the State Higher Education Council,

14

झारखण्डगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

(xvii) 'AISHE' means the All India Survey on Higher Education initiated by the Ministry of Human

Resource Development, Government of India,

(xviii) 'NAAC means the National Assessment and Accreditation Council, established for rating the

"quality status" of a particular higher education institution.

(xix) 'MIS'(Management Information System) means management information systems to provide

efficiency and effectiveness of strategic decision making.

3. Constitution of the Council:

(i) The Government may by notification, constitute, with effect from such date as may be specified

therein, a council to be called the Jharkhand State Higher Education Council.

(ii) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and

shall by that name sue and be sued.

(iii) The Council shall have the power to acquire and hold, both movable and immovable property

and subject to the provisions of this Act, and the rules made there under to transfer any

property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act.

(iv) The headquarter of the council shall be located at Ranchi.

4. Responsibilities and functions of the Council:

(i) The Council shall have the following responsibilities and functions, namely:-

(a) To render advice to the Government, State Universities, Private Universities, and other

institutions of higher education in the state:

(b) to coordinate the roles of the Government, State Universities, Private Universities, and

Apex Regulatory Agencies in higher education within the state;

- (c) to provide common facilities in higher education without impairing upon the autonomy of other institutions of higher education;
- (ii) For the furtherance of the above responsibilities and functions, the Council shall specifically undertake the following:-
- (a) formulate and evolve State Higher Education plan (SHEP) for the development of higher education, *suomoto* or on the suggestion from Government or request from State Universities or other Institutions;
- (b) provide support to State Institutions and affiliated institutions for formulation production of their plans and implementing them;
- (c) monitor the implementation of State Higher Education Plan;
- (d) compile and maintain periodic statistics at state and institutional level and assist in All India Survey on Higher Education (AISHE);
- (e) create and maintain Management Information system (MIS);
- (f) evaluate Institutions on the basis of norms developed by national level higher education agencies;
- (g) suggest improvements in curriculum and syllabus accordance with the changing societies and academic requirements and maintain quality of curriculum;
- (h) to ensure quality of examinations and suggest reforms in examination;
- (i) undertake necessary steps for establishing inter-linkage between research and learning process;
- (j) protect the autonomy of state institutions and review periodically the statutes, ordinances and regulations of the Universities in the state and suggest appropriate improvement for the realization of the objects of social justice and academic excellence in education, and advise the universities or other institute of higher education on statute, ordinance or regulation formulation;
- (k) provide approval to setting up new institutions of higher education;
- (l) suggest accreditation reforms measures in consultation with National Assessment and Accreditation Council (NAAC);
- (m) advise state government on strategic investments in higher education;
- (n) evolve guidelines for linkages of an academic nature between higher education institutions in the State and institutions within and outside the country;
- (o) make proposals for the generation and utilization of funds with the objective of this Act;
- (p) evolve general guidelines for the release of grants by the Government or any agency authorized by the government and disburse funds to the universities and colleges on the basis of State Higher Education Plan (SHEP);
- (q) evolve methodology for timely transfer of the funds earmarked for the State Universities and other institution of higher education;
- (r) hold discussions, conduct workshops, seminars with the objective of facilitating the widest possible consultancies with experts and stakeholders for formulating the policies and on higher education and facilitating them proper implementation;
- (s) provide a forum for the interaction among the academy, industries, agriculture and

झारखंड गजट (असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

science sectors,

(t)

co-ordinate various programmes being promoted and undertaken by Central and State Government and national level apex regulatory bodies in the territory of India.

5. Composition of the council.

The Council shall consist of the following members, namely:

(i) The Chairman

(ii) The Vice Chairman

(iii) Executive Director (Member Secretary)

(iv)

The Principal Secretary, Department of Higher & Technical Education; (v) Five members to be nominated by the Chancellor who are persons of scholarly pursuit, one each belonging from the field of art & culture, science & technology, civil society, industry, and vocational field.

(vi) Five members to be nominated by the Government who are persons of scholarly pursuit, one each belonging from the field of art & culture, science & technology, civil society, industry, vocational field.

(vii) Three Vice-Chancellors of the state universities to be nominated by the Chancellor in rotation of three years.

(viii) One Vice Chancellor of Private University established in the State.

(ix) One Vice Chancellor of Technical University established in the State.

16

झारखंड गजट (असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

(x) Two Principals of Autonomous Colleges to be nominated by the Chancellor in rotation of two years.

(xi) Three members co-opted by the Council who are persons of scholarly pursuit.

(xii) One nominee of the Government of India to be nominated by the Ministry of Human Resource Development.

6. The Chairman:

(i) The Chairman will be preferably an eminent academic or public intellectual with proven

leadership qualities.

(ii) The Chairman will be selected by a committee consisting of Chief Minister, Speaker of the

Legislative Assembly, Leader of the Opposition, on the basis of recommendation of short-listed

candidates made by a three - member search-cum-selection committee constituted by the

State Higher Education Council. The Council shall nominate two eminent academic / public

intellectual with proven record while the State will nominate one person. The State nominee will chair.

(iii) The Chairman shall be appointed by the Government as whole time officer.

(iv) The Chairman will have a non-extendable term of five years or till he attains an age of 70 years

whichever is earlier.

- (v) The Chairman may be removed through a vote of non-confidence expressed by at least two -
third members present and voting with a quorum of three - fourth members.
- (vi) The Chairman shall have the right to call for report on any matter pertaining to the affairs of the
council and offer suggestions for the improvement of the functioning of the Council.
- (vii) The Chairman shall preside over the meetings of the Council and the Executive Committee.
- (viii) The salaries and allowances payable to the Chairman shall be the same as that of Vice-Chancellor of
University. If he is a retired person, his pay shall be reduced to that of his pension.

7. The Vice Chairman:

- (i) The Vice Chairman shall be an eminent academic administrator with proven record. In case of non-academic person, the Vice Chairman could be a professional from industry etc. with
sufficient experience in the sector.
- (ii) The Government will appoint the Vice Chairman on the recommendation of a Search Committee
consisting of Chairman of the Council (as Chair) and two other members, one nominated by the
Council and one by the Government.
- (iii) The Vice- Chairman will have one non-extendable term of five years or till he attains an
age of 70 years.
- (iv) The Vice -Chairman may be removed by the Chairman or by the recommendation of the
Council.
- (v) The Vice Chairman shall preside over the meetings of the Council in the absence of the
Chairman.
- (vi) The salaries and allowances payable to the Vice Chairman shall be the same as that of a
Professor of a University. If he is retired person, his pay shall be reduced to that of his pension.

झारखंडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

17

8. The Executive Director:

- (i) The State Project Director of Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan will be *ex officio* Executive
Director of the Council.
- (ii) The Executive Director will be the Member Secretary of the Council and shall be responsible for coordination of the functioning of the council,
- (iii) The Executive Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

9. Officers of the Council:

The following shall be the officers of the Council namely:-

- i. The Chairman

- ii. The Vice Chairman
- iii. The Executive Director,
- iv. Administrative Officer
- v. Finance Officer

10. Administrative Officer:

- (i) The Administrative Officer shall be a whole-time officer of the Council and will be a person on deputation from University.
- (ii) The Administrative Officer shall be a person having at least fifteen years experience in teaching in a college or post graduate department of university and at least five years experience in University administration.
- (iii) The Administrative Officer shall be appointed by the Council.
- (iv) The Administrative Officer shall be in charge of general administration and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Chairman.
- (v) The Administrative Officer shall be entitled to receive deputation allowance over and above his pay and allowances which he was drawing in his parent University.

11. Finance Officer:

- (i) The Finance Officer shall be a whole-time officer of the Council and will be a person on deputation from University.
- (ii) The Finance Officer shall be a person having fifteen years of teaching experience and financial administration, and sound knowledge of accountancy, auditing and budgetary procedures.
- (iii) The Finance Officer shall be appointed by the council.
- (iv) The Finance Officer shall be In-charge of Accounts Department and will be responsible for maintaining the accounts of the council and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him/her by the Chairman.
- (v) The Finance Officer shall be entitled to receive deputation allowance over and above his pay and allowances which he was drawing in his parent University.

12. State Project Directorate (SPD):

The State Government will constitute a State Project Directorate with following composition.

18

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

- (i) Composition: The SPD will consist of State Project Director and such adequate support staff as may be required for the effective functioning of the State Project Directorate.
- (ii) Functions: The SPD will perform the following functions-
 - *Overseeing project implementation at the State level;
 - *Maintain statistical data and MIS report; and
 - *Engage Project Auditors as required.

13. Technical Support Group:

- (i) The State Higher Education Council may appoint a Technical Support Group consisting of experts.

- (ii) The composition of the Technical Support Group will be decided by the Council.
- (iii) The function of the Technical Support Group will be to (a) monitor flow of funds and information, (b) generate MIS reports as required, and (c) provide operational support to the Council.

14. Terms and Conditions of nominated members:

- (i) Each nominated and co-opted member will normally have a term of six years, provided that
 - one - third of the members will retire every two years on the basis of age, and the vacancy will be filled by the Chancellor, if the retiring member is Chancellor's nominee, or by the Government, if the retiring member is a Government nominee, or by the council, if the retiring member is a co-opted member.
- (ii) At any point of time, twenty members of the Council should be from the state and five members must be individual of national eminence (outside the State).
- (iii) The nominated and co-opted member may by writing under his hand addressed to the Chairman of the Council resign his membership but he/she shall continue to remain member until his/her resignation is accepted in writing by the Chairman of the council.
- (iv) The nominated and co-opted member shall be eligible for such rate of travelling allowance, daily allowance and sitting fee as may be prescribed.
- (v) Subject to the provision of this section the other terms and condition of the service shall be such as may be prescribed.

15. Disqualifications

- (i) No person shall be qualified for nomination or to continue as a member of the Council, if on the date of such nomination he is:
 - (a) of unsound mind;
 - (b) adjudicated as an un-discharged solvent;
 - (c) sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude;
 - (d) directly or indirectly by himself or his partner has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of the council;
 - (e) a person who has been terminated from any Government or University Services on grounds of misconduct or negligence.
- (ii) In case of dispute or doubt as to whether a person is disqualified under sub-section (1) the decision of the Chairman shall be final.

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

- (iii) Save as otherwise pointed in this Act, no person who is not a graduate of any University established by law shall be eligible for nomination as a member of the council under this Act.

16. Meeting of Council:

- (i) The Council shall meet as often as may be necessary at such time and place and observe such rules of procedures as may be provided in regulation, but it shall meet at least once in three months.
- (ii) It shall have the power to act, notwithstanding any vacancy in the membership or any defect in the constitution thereof, and the proceedings of the council shall be valid notwithstanding that some person, who was not entitled to be a member, had attended, or otherwise had taken part in the proceedings of the council.
- (iii) The meeting of the Council shall be convened by the Executive Director on the advice of the Chairman.
- (iv) The quorum of the meeting of the council shall be one third of the total members of the council and division may be taken in the meetings by simple majority of those present and voting.

17. Staff of Council:

The Council shall appoint such number of employees as may be necessary for the efficient performance of its functions. The terms and conditions of service of the employees of the council shall be such as may be provided in the regulations.

18. Funds of the Council:

- (i) The funds of the Council shall include all sums which may, from time to time, be paid to it by the Government and all other receipts including any sum from the Central Government, or any other authority, institutions or persons.
- (ii) The Government may pay to the Council every financial year such sums as may be considered necessary for the functioning of the council and for the discharge of its responsibilities and duties.
- (iii) All expenditure incurred by the Council under or for the purposes of this Act shall be defrayed from out of the fund and any surplus remaining, after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.

19. Annual Accounts and Audit:

- (i) The accounts of the Council shall be maintained in such manner and in such form as may be prescribed,
- (ii) The Council shall prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed,
- (iii) The accounts of the Council shall be audited once in a year by such auditor as the Government may appoint or depute in this behalf,
- (iv) The Executive Director to the Council shall cause the annual audit report to be printed and shall place such report before the council for consideration at its next meeting,
- (v) The Council shall take appropriate action forthwith to remedy any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report,

20

झारखण्डगजट(असाधारण) बुधवार, 25 मई, 2016

- (vi) The accounts of the Council as certified by the auditor together with the audit report along with the remarks of the Council there on shall be forwarded to the Government within such time as may be prescribed.

20. Annual Report:

The Council shall prepare for every year a report of its activities under this Act during that year and submit the report to the Government.

21. Members and Staff of the Council to be public servants:

The Chairman, Vice Chairman, Executive Director, Member, Officers and Staff of the Council shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act or any rule or regulations or order or direction made or issued under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860).

22. Power to make regulations:

The Council with prior approval to the Government may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and rules made there under for carrying out all or any of the purposes of this Act.

23. Power to make rules:

(i) The Government may, by notification, make rules, for carrying out all or any purposes of this Act.

(ii) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the state legislature whole it is a session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislature Assembly makes any amendment in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such form as amended or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such amendment or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

24. Power to remove difficulties:

(i) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, as occasion may require, do nothing not inconsistent with the provisions of this Act which appears to them to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

(ii) Every order issued under the sub section (1) shall, as soon as may be after it is made laid before the legislative Assembly.

झारखंड राॉयपाल के आदेश से,

ढदनेश कुमार

िसंह,

धधान सिचव-सह-

धविध परामशक

धविध (धवधान) धवभाग,

झारखंड, राँची।

झारखंड राजकअय मुकुणालय, राँची तारा
धकािशत एवं मुठुंत, झारखंड गजट
(असाधारण) 366—50 ।